



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]  
No. 539]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2008/वैशाख 3, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2008/VAISAKHA 3, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2008

का.आ. 913(अ).—केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 के नियम 3 के उप-नियम (2), नियम 4 और नियम 18 के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के लिए सलाहकार समिति का गठन करती है और उक्त समिति में, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करती है, अर्थात् :-

- (1) श्रम मंत्री — अध्यक्ष
- राजस्थान सरकार,  
जयपुर
- (2) कल्याण आयुक्त,  
भारत सरकार, अजमेर
- (3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त,  
(केन्द्रीय) अजमेर
- (4) श्री हीरा लाल रैगर, एमएलए,  
निवाई निर्वाचन क्षेत्र,  
जिला-टांक, राजस्थान
- नियोजकों के प्रतिनिधि :
- (5) श्री एस. आर. पाण्डेय,  
उपाध्यक्ष (कार्मिक और  
मानव संसाधन),  
जे. के. लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स,  
पोस्ट-जे. के. पुरम,  
जिला-सिरोही, राजस्थान

(6) श्री एस. आर. शर्मा, — सदस्य  
महाप्रबंधक (खनन और विभाग  
का भारसाधक),  
मैसर्स विरला सीमेंट वर्क्स,  
पोस्ट-चित्तौड़गढ़, राजस्थान

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

- (7) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, — सदस्य  
जनरल सैक्रेटरी,  
भारतीय मजदूर संघ,  
42, पटेल कालोनी,  
सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,  
जयपुर, राजस्थान
- (8) श्री बी. एल. सैनी, — सदस्य  
उपसचिव,  
हिन्द मजदूर यूनियन,  
रेलवे स्टेशन, जयपुर, राजस्थान
- (9) श्रीमती शांति देवी चौधरी, — सदस्य  
साहू नगर सीमेंट फैक्टरी,  
सवाई माधोपुर, राजस्थान
- 2. कल्याण प्रशासक, श्रम कल्याण संगठन, अजमेर, सलाहकार  
समिति के सचिव होंगे ।
- 3. सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) की पदावधि तीन वर्ष  
होगी ।
- 4. उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय अजमेर में होगा ।

[सं. यू-19012/03/2006-डब्ल्यू. II(सी)]

अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2008

**S.O. 913(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), read with sub-rule (2) of rule 3, rule 4 and rule 18 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund for the State of Rajasthan and appoints the following persons to the said Committee with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

(1) Minister of Labour, Government of Rajasthan, Jaipur	— Chairman
(2) Welfare Commissioner, Government of India, Ajmer	— Vice-Chairman ( <i>ex-officio</i> )
(3) Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer	— Member ( <i>ex-officio</i> ) Central Government Representative
(4) Shri Heera Lal Raiger, M.L.A. Niwai Constituency, District-Tonk, Rajasthan	— Member Member of the Legislative Assembly

**Representatives of Employers'**

(5) Shri S.R. Pandey, Vice-President (Personnel and Human Resources), J. K. Laxmi Cement Works, Post-J. K. Puram, Dist.-Sirohi, Rajasthan	— Member
--	----------

(6) Shri S.R. Sharma, General Manager (Mining and Department In charge), Messers Birla Cement Works, Post-Chanderiya, Dist.-Chittorgarh, Rajasthan	— Member
---	----------

**Representative of Employees' :**

(7) Shri Rajendra Prasad Sharma, General Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh, 42, Patel Colony, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan	— Member
(8) Smt. B.L. Saini, Deputy Secretary, Hind Mazdoor Sabha, North West Union, Railway Station, Jaipur, Rajasthan	— Member
(9) Smt. Shanti Devi Choudhary, Sahoo Nagar Cement Factory, Sawai Madhopur, Rajasthan	— Member Woman Representative.

2. Welfare Administrator, Labour Welfare Organisation, Ajmer shall be the Secretary of the Advisory Committee.

3. The headquarters of the said Advisory Committee shall be at Ajmer.

4. The tenure of the members (other than *ex-officio* members) shall be for a period of three years.

[ No. U-19012/03/2006-W. II(C) ]

ANIL SWARUP, Director General  
(Labour Welfare)/Jt. Secy.